झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
रिट याचिका संख्या 2076/2023

दीप नारायण बाउरी

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, पुलिस महानिरीक्षक, त्वरित कार्रवाई बल, सीआरपीएफ, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली 110066
2. पुलिस महानिरीक्षक, सीआरपीएफ (आरएएफ), देहरादून, उत्तराखंड
3. कमांडेंट संख्य 106 बटालियन आर.ए.एफ. सी.आर.पी.एफ., जमशेदपुर, झारखंड

... विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिएः श्री अमित सिन्हा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी के लिए: श्री मण्डन प्रसाद, सी.जी.सी

_ _ _ _ _

09/15.12.2023 याचिकाकर्ता ने इस अदालत में उत्तरदाताओं के खिलाफ 08.06.2019 को कमांडेंट नंबर 106 बटालियन आरएएफ, सीआरपीएफ, जमशेदपुर द्वारा पारित आदेश और 03.10.2019 को उप पुलिस महानिरीक्षक, सीआरपीएफ (आरएएफ), देहरादून, उत्तराखंड द्वारा पारित आदेश को रद्द एवं निरस्त करने की प्रार्थना के साथ संपर्क किया है।

इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता पुलिस महानिरीक्षक, त्वरित कार्रवाई बल, सीआरपीएफ (आरएएफ), नई दिल्ली द्वारा पारित जनवरी 2020 के महीने का शून्य दिनांक का आदेश रद्द करने की प्रार्थना करता है।

याचिकाकर्ता ने यह भी प्रार्थना की है कि उपर्युक्त आदेशों को रद्द करने के बाद, उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को सेवाओं में पुनः बहाल करने और सभी परिणामी लाभों के साथ निर्देश दिया जाए।

2. याचिकाकर्ता का मामला संकीर्ण दायरे में है। जबकि याचिकाकर्ता सीआरपीएफ के तहत कांस्टेबल के रूप में कार्यरत था, उसे एक कारण-बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने अपनी पहली पत्नी, उषा देवी के जीवित रहते हुए, एक दूसरे विवाह को संपन्न किया है, जो कि एक रेशमा देवी के साथ है। याचिकाकर्ता ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वह सीआरपीएफ के नियम 11(1) के प्रावधानों से अनजान था और जब उसने 05.01.2016 को अपनी पहली पत्नी से तलाक का समझौता किया, तो उसे लगा कि अब वह दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए उसने अपनी दूसरी पत्नी रेशमा देवी से विवाह किया। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा कारण-बताओ उत्तर में उठाए गए कारण से संतुष्ट न होने पर, उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की और जांच अधिकारी नियुक्त किया। विभागीय कार्यवाही में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और याचिकाकर्ता को अपना मामला प्रस्तुत करने और उत्तरदाताओं के गवाहों का क्रॉस-एक्सामिनेशन करने का अवसर दिया गया, जिसका उसने उचित रूप से लाभ उठाया। इसके बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने सीआरपीएफ अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) और सीआरपीएफ नियम, 1955 के नियम 27 की शक्ति का उपयोग करते हुए याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने का दंडात्मक आदेश पारित किया, यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता ने यह महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है कि उसने अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी की है, जो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अनुमेय नहीं है और इसे गंभीर दुराचार माना गया।

दंडात्मक आदेश से असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने अपील की लेकिन वह खारिज कर दी गई और दंडात्मक आदेश की पुष्टि की गई। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उसने अपनी पहली पत्नी के खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(बी) के तहत आपसी सहमति से तलाक का निर्णय प्राप्त किया है, जो 29.11.2018 को पारित वैवाहिक (तलाक) मुकदमा संख्या 51/2018 में दिया गया था, जिसे उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता को सेवा से हटाते समय ध्यान में नहीं रखा।

प्रत्यर्थियों की उक्त कार्रवाई से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश किया गया है।

3. श्री अमित सिन्हा, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता,विवादित आदेशों को इस आधार पर चुनौती देते हैं कि उत्तरदाताओं ने यह महत्वपूर्ण तथ्य नहीं माना कि याचिकाकर्ता ने पहले ही अपनी पहली पत्नी से एक समझौते के माध्यम से सहमति प्राप्त कर ली थी और उसके बाद दूसरी शादी की है, और इस प्रकार, उसने सीआरपीएफ अधिनियम और सीआरपीएफ नियमों के तहत कोई अपराध नहीं किया है। अधिवक्ता आगे तर्क करते हैं कि याचिकाकर्ता ने 14 वर्षों से अधिक की बेदाग सेवा की है और केवल उसकी पहली पत्नी द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर कि याचिकाकर्ता ने दूसरी शादी की है, उत्तरदाताओं ने उसे सेवा से हटाने की गंभीर सजा दी है। अधिवक्ता यह भी बताते हैं कि अपील प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता द्वारा अपील में उठाए गए कारणों पर विचार नहीं किया और यांत्रिक रूप से दंडात्मक आदेश को पुष्टि करते हुए उसे खारिज कर दिया। अधिवक्ता इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उपर्युक्त तथ्यों और कारणों के लिए, विवादित आदेशों को रद्द और निरस्त किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में पुनः बहाल करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

4. प्रतिवादी ने जवाबी हलफनामा दायर किया है। श्री मदन प्रसाद, प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्क का जोरदार विरोध करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि विभागीय जांच कानून के अनुसार की गई थी और इसमें कोई गलती नहीं है। याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों के गवाहों को क्रॉस-एक्सामिन करने का पर्याप्त अवसर देने के साथ निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई दी गई थी, और इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं हुआ है। जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से प्रमाणित पाया, तब अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने हटाने का आदेश जारी किया। विवादित आदेशों में कोई अवैधता या कमजोरी नहीं है। अनुशासनात्मक प्राधिकरण का आदेश अपीलीय प्राधिकरण तक पुष्टि किया गया था और इस प्रकार, याचिका को सीधे खारिज करना उचित है। अधिवक्ता आगे तर्क करते हैं कि याचिकाकर्ता ने यह तथ्य छिपाया है कि उसने अपनी पहली पत्नी की जीवनकाल में दूसरी शादी की है, जो हिंदू विवाह अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत अनुमति नहीं है।

5. फिर भी, पक्षों की प्रतिकूल प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय इस विचार पर है कि याचिकाकर्ता ने दूसरी शादी की है, जो विवाद में नहीं है। याचिका में निपटाने के लिए जो मुद्दे शामिल हैं, वे हैं:

I) क्या याचिकाकर्ता द्वारा केंद्रीय सिविल सेवाओं (व्यवहार) नियम, 1964 के नियम 21 का पूर्ण उल्लंघन करते हुए दूसरी शादी करने से सेवा से हटाने का आदेश आवश्यक है?

II) क्या दूसरी शादी के तथ्य को छिपाने से सेवा से हटाने की बड़ी सजा आकर्षित होती है?

III) क्या पहली पत्नी के साथ समझौते के बावजूद तलाक के निर्णय से पहले दूसरी शादी करने पर सेवा से हटाना ही एकमात्र सजा है?

6. रिकॉर्ड पर लाए गए दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता ने दूसरी शादी की है।

दूसरी शादी का आयोजन तलाक के निर्णय से पहले हुआ था, लेकिन साथ ही यह भी नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता और उसकी पहली पत्नी के बीच तलाक का कोई समझौता नहीं था।

7. अब, यह प्रश्न कि क्या बहुविवाह करने का प्रभाव सेवा से बर्खास्तगी की उच्च सजा को आमंत्रित करता है। बहुविवाह करने का प्रभाव निश्चित रूप से संबंधित व्यक्ति के आचार संहिता से संबंधित वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन इसका किसी भी प्रकार के अवज्ञा, कर्तव्य की अनदेखी या किसी कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही और/या अनुशासित बल के सदस्य के रूप में अन्य दुराचार से कोई संबंध नहीं हो सकता।

8. जहाँ तक सेवा के दौरान दूसरी शादी करने का प्रश्न है, यह केंद्रीय सिविल सेवाओं (व्यवहार) नियम, 1964 के नियम 21 द्वारा नियंत्रित होता है, जो बीएसएफ पर भी लागू होते हैं। यह नियम इस प्रकार है:-

> ***"21. विवाहों के संबंध में प्रतिबंध*** *-*
> *(1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा, जिसका पति या पत्नी जीवित हो; और*
> *(2) कोई सरकारी कर्मचारी, जिसका पति या पत्नी जीवित हो, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा:*
> *प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार किसी सरकारी कर्मचारी को उपधारा (1) या (2) में संदर्भित किसी ऐसे विवाह में प्रवेश करने या अनुबंध करने की अनुमति दे सकती है, यदि वह संतुष्ट है कि*
> *(क) ऐसा विवाह उस सरकारी कर्मचारी और विवाह के दूसरे पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमेय है; और*
> *(ख) ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं।*
>
> *(3) सरकारी कर्मचारी जो किसी व्यक्ति से शादी कर चुका है या शादी करता है, जो भारतीय राष्ट्रीयता का नहीं है, उसे तुरंत इस तथ्य की सूचना सरकार को देनी होगी।*
> *नियम 21 के उप-नियम (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी, जिसका पति या पत्नी जीवित हो, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा। इस नियम का प्रावधान, बीएसएफ नियमों के नियम 7 के प्रावधान की तरह, केंद्रीय सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी सरकारी कर्मचारी को दूसरी शादी करने की अनुमति दे सकती है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा विवाह व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमेय है और दूसरी शादी करने के लिए आधार मौजूद हैं।*

जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, अपेक्षाकृत हल्की सजा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है, क्योंकि याचिकाकर्ता को पुनः बहाल करना और उसे एक मौका देना न्याय के हित में होगा। आखिरकार, आजीविका का प्रश्न भी शामिल है। इन परिस्थितियों में, अपेक्षाकृत हल्की सजा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है। एक और तथ्य, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वह मानव समस्या है, कि क्या किसी व्यक्ति को दूसरी शादी के लिए पूर्व अनुमति न लेने पर इतनी कठोर सजा दी जानी चाहिए। यह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसमें पहले पत्नी, दूसरी पत्नी और बच्चों पर पड़ने वाले परिणामों को ध्यान में रखा जाएगा।

जहाँ तक दुराचार का संबंध है, यह एक स्पष्ट और सरल मामला है। हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा की गई गलती यह थी कि उसने दूसरी शादी के तथ्य को अधिकारियों के सामने प्रकट नहीं किया। इसलिए, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि सेवा से हटाने की सजा दोनों पत्नियों और बच्चे को बिखेर देगी और उन्हें दरिद्रता और अभाव की स्थिति में छोड़ देगी।

9. इसी तरह का मुद्दा **मनोज कुमार मंडल बनाम झारखंड राज्य और अन्य, 2014 एससीसी ऑनलाइन झार 18** के मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया।

10. यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बैठते हुए सामान्यतः उन सजा आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करता है जो अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किए गए हैं। सामान्यतः, यह न्यायालय उन साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन नहीं करेगा जो पहले ही विभागीय कार्यवाही में मूल्यांकित किए जा चुके हैं और जिन पर एक निष्कर्ष निकाला गया है, लेकिन यदि निष्कर्ष विकृत हैं और सजा आदेश न्यायिक विवेक को झकझोर देता है, तो न्यायालय के पास हस्तक्षेप करने की पूरी शक्ति है।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में **निदेशक जनरल पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल बनाम राजेंद्र कुमार दुबे, 2020 एससीसी ऑनलाईन एससी 954** में, **अनुच्छेद-33 और 34** में इस प्रकार कहा है:-

> *"33. राज्य आंध्र प्रदेश बनाम एस. श्री राम राव मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय उन अधिकारियों के निर्णय पर अपील अदालत नहीं है जो किसी सार्वजनिक कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच करते हैं। उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र अपने रिट अधिकार क्षेत्र के तहत साक्ष्यों की समीक्षा करना और साक्ष्यों पर स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचना नहीं है। हालाँकि, उच्च न्यायालय तब हस्तक्षेप कर सकता है जब विभागीय प्राधिकरण जो अव्यवस्थित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ असंगत हो, जहाँ निष्कर्ष बिना किसी साक्ष्य के आधारित हों, जो यह निष्कर्ष निकालने के लिए उचित रूप से समर्थन कर सके कि अव्यवस्थित अधिकारी आरोप का दोषी है, या जांच की विधि को निर्धारित करने वाले वैधानिक नियमों का उल्लंघन किया गया हो, या प्राधिकरण कुछ बाहरी विचारों से प्रेरित होकर उचित निर्णय तक पहुँचने में असफल रहे हों, या अप्रासंगिक विचारों से प्रभावित हो गए हों, या जहाँ निष्कर्ष अपने आप में इतना पूरी तरह से मनमाना और मनमौजी हो कि कोई भी उचित व्यक्ति कभी भी उस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता। हालाँकि यदि जांच सही ढंग से की गई है, तो विभागीय प्राधिकरण तथ्यों का एकमात्र न्यायाधीश होता है, और यदि कुछ वैधानिक साक्ष्य हैं जिन पर निष्कर्ष आधारित हो सकते हैं, तो उस साक्ष्य की पर्याप्तता या विश्वसनीयता एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे उच्च न्यायालय में रिट याचिका में उठाने की अनुमति दी जा सकती है।"*

"34. ये सिद्धांत राज्य आंध्र प्रदेश बनाम चित्रा वेंकट राव मामले में फिर से दोहराए गए। अनुच्छेद 226 के तहत सर्टियरी का रिट जारी करने का अधिकार एक पर्यवेक्षी अधिकार है। न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं करता है। किसी निम्न अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा साक्ष्यों के मूल्यांकन पर पहुँचे गए तथ्यों के निष्कर्षों को रिट कार्यवाही में फिर से नहीं खोला या प्रश्न नहीं किया जाता है। रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली कानूनी त्रुटियों को रिट अदालत द्वारा सुधारा जा सकता है, लेकिन तथ्यों की त्रुटियों को, चाहे वे कितनी भी गंभीर क्यों न हों, नहीं सुधारा जा सकता। यदि यह दिखाया जाता है कि तथ्य के निष्कर्ष को दर्ज करते समय, ट्रिब्यूनल ने स्वीकार्य और महत्वपूर्ण साक्ष्य को गलत तरीके से स्वीकार करने से इनकार किया है, या गलत तरीके से अस्वीकार्य साक्ष्य को स्वीकार किया है। ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किया गया तथ्य का निष्कर्ष इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत किया गया महत्वपूर्ण साक्ष्य निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त या अपर्याप्त है। किसी बिंदु पर प्रस्तुत साक्ष्य की पर्याप्तता या पर्याप्तता और उस निष्कर्ष से निकाले जाने वाले तथ्यों का अनुमान ट्रिब्यूनल के विशेष अधिकार क्षेत्र के भीतर आते हैं।"

इसके अलावा, **संघ भारत और अन्य बनाम पी. गुणाशेखरन, (2015) 2 एससीसी 610** में रिपोर्ट की गई मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अवलोकन किया है कि, "उच्च न्यायालय अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 226 और 227 के तहत साक्ष्यों के मूल्यांकन में नहीं जा सकता या यदि जांच की प्रक्रिया कानून के अनुसार की गई हो तो निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, या साक्ष्य की विश्वसनीयता/पर्याप्तता में नहीं जा सकता, या यदि निष्कर्षों पर कुछ कानूनी साक्ष्य आधारित हैं तो हस्तक्षेप नहीं कर सकता, या तथ्यों की त्रुटियों को सुधार नहीं सकता चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न हो, या दंड की अनुपातिता में नहीं जा सकता जब तक कि यह न्यायालय की विवेक को झकझोर न दे।"

भारत संघ बनाम पी. गुणाशेखरन (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभागीय कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा देखे जाने के लिए कुछ तत्व निर्धारित किए हैं, जो निम्नानुसार हैंः

"12. स्थापित स्थिति के बावजूद, यह दुखदायी है कि उच्च न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही में एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य किया है, यहाँ तक कि जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन भी किया है। अभियोग पर निष्कर्ष को अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया था और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था। अनुशासनात्मक कार्यवाही में, उच्च न्यायालय एक दूसरी पहली अपील अदालत के रूप में कार्य नहीं कर सकता और न ही कर सकता है। उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन में नहीं जाएगा। उच्च न्यायालय केवल यह देख सकता है कि:"

(क) जांच एक सक्षम प्राधिकरण द्वारा की गई है;

(ख) जांच उस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है;

(ग) कार्यवाही के संचालन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है;

(घ) प्राधिकरणों ने मामले के साक्ष्य और गुणों से संबंधित कुछ बाहरी विचारों के कारण निष्पक्ष निष्कर्ष पर पहुँचने में असमर्थता दिखाई है;

(घ) प्राधिकरणों ने स्वयं को अप्रासंगिक या बाहरी विचारों से प्रभावित होने की अनुमति दी हैं;

(ङ) निष्कर्ष अपने आप में इतना पूरी तरह से मनमाना और मनमौजी है कि कोई भी उचित व्यक्ति कभी भी ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता;

(च) अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने स्वीकार्य और महत्वपूर्ण साक्ष्य को गलत तरीके से स्वीकार करने में असफलता दिखाई;

(छ) अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने अस्वीकार्य साक्ष्य को गलत तरीके से स्वीकार किया, जिसने निष्कर्ष को प्रभावित किया;

(ज) तथ्य का निष्कर्ष बिना किसी साक्ष्य के आधारित है।

12. वर्तमान मामले में, पहली पत्नी और याचिकाकर्ता लंबे समय से अलग थे और तलाक प्राप्त करने के लिए एक समझौता किया गया था, हालाँकि तलाक का निर्णय दूसरी शादी के आयोजन के बाद दिया गया। इसी कारण, 03.10.2019 की हटाने का आदेश आरोपों के अनुपात में असंगत है। अनुशासनात्मक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण ने यह ध्यान नहीं दिया कि तलाक का निर्णय जारी किया गया था और इसे विवादित आदेश पारित करने से पहले ध्यान में लिया जा सकता था। प्रतिवादियों ने यह कोई विचार नहीं दिखाया कि तलाक का निर्णय अस्तित्व में आया है और वहाँ एक न्यायिक अलगाव था। चूंकि सेवा से हटाने की सजा दोनों पत्नियों और बच्चे को बिखेर देगी और उन्हें दरिद्रता और अभाव की स्थिति में छोड़ देगी, इसलिए बर्खास्तगी का आदेश न्यायिक विवेक को झकझोर देता है और इस प्रकार, यह सहजता से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुपात में असंगत है।

13. उपरोक्त अवलोकनों, नियमों, दिशानिर्देशों और कानूनी प्रस्तावों के अनुक्रम में, 08.06.2019 की विवादित आदेश (अनुबंध 4) और जनवरी, 2020 की विवादित आदेश (अनुबंध 8) को यहाँ रद्द किया जाता है और इसे रद्द कर दिया जाता है। मामले को प्रतिवादियों के पास वापस भेजा जाता है ताकि वे इसे नए सिरे से पुनर्विचार करें और बर्खास्तगी/हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के अलावा कोई अन्य सजा पारित करें।

14. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(डॉ. एस एन पाठक, न्यायधीश)

आरसी/के

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|